

नौ लाख करोड़ रुपये से बड़ा हो सकता है आकार

योगी सरकार का दसवां बजट आज

लखनऊ, विशेष संवाददाता। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को सुबह 11 बजे विधान सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार का 10वां बजट पेश करेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने के पहले यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपये के पार होने की उम्मीद है। मंगलवार को वित्त मंत्री ने बजट पर दस्तखत कर दिए हैं।

विधान भवन स्थिति अपने कार्यालय में बजट पर हस्ताक्षर करने के बाद सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि बजट प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं, विकास की जरूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार की विकासशील सोच और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतिबिंब है। अगले साल प्रस्तावित चुनाव के मद्देनजर बजट के लोकलुभावन होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के अपने लक्ष्य पर भी मजबूती से आगे बढ़ती दिखाई देगी।

मानदेय बढ़ेगा, एरियर के भी होगा पैसा : बजट में सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में इजाफा करती दिख सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें एरियर भी देने के आदेश दिए थे। तकरीबन 25 हजार अनुदेशक हैं और 1.43 लाख शिक्षामित्र प्रदेश में कार्यरत हैं। माना जा रहा है कि करीब 250 करोड़ रुपये इस मद में दिए जा सकते हैं।

➤ बजट सत्र P11

विधानसभा चुनाव से पूर्व योगी का आखिरी बजट



35 सौ करोड़ मिल सकते हैं नई टाउनशिप विकसित करने के लिए
40 लाख से अधिक युवाओं का टेबलेट बांटने का लक्ष्य है सरकार का

■ विधानसभा में वित्त मंत्री 11 बजे सुबह पेश करेंगे बजट

कैबिनेट में आज बजट व सीएजी रिपोर्ट पर लगेगी मुहर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली इस बैठक में बुधवार को विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में यूपीसीडा, लखनऊ मेट्रो के निर्माण एवं संचालन, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों का विकास एवं आवंटन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और आयुष विभाग से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने संबंधी प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी जाएगी।

क्षेत्रीय विकास

₹2000 करोड़ का प्रावधान पूर्वांचल और बुंदेलखंड में नई परियोजनाओं के लिए संभव

बुनियादी ढांचा

₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आवंटित की जा सकती है।

पेंशन में वृद्धि

₹1000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह वृद्धावस्था, निराश्रित महिलाओं व दिव्यांगों की पेंशन की जा सकती है।

कानून व्यवस्था

₹45000 करोड़ से अधिक गृह विभाग को मिल सकते हैं, साइबर सुरक्षा व एआई पर जोर।

महिला सशक्तिकरण: मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी है।



कानून-कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे: योगी

बाराबंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी ढांचे की बात करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि कयामत का दिन कभी आने वाला नहीं है। कानून-कायदे में रहने वाले फायदे में रहेंगे। अगर कोई कानून तोड़ने का सपना देख रहा है तो वह कभी पूरा नहीं होगा। योगी ने ऐलान किया कि बाराबंकी को जल्द ही विकास प्राधिकरण और लोधेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कॉरीडोर मिलेगा।

➤ ब्योरा P12